पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 822

थाना संख्या-457 वर्ष-2015 थाना-बिहार जिला-नालंदा से उद्भुत

विवेक कुमार उर्फ विवेक उर्फ मोदी उर्फ राम विवेक कुमार, आयु 35 वर्ष, पुरुष, पिता नंद किशोर प्रसाद, निवासी गाँव-मजीदपुर/माजिदपुर, पी. एस.-मानपुर, पोस्ट-इटौरा, जिला-नालंदा, बिहार, पिन-803107

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

के साथ

2022 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 99

थाना संख्या-457 वर्ष-2015 थाना-बिहार जिला-नालंदा से उद्भुत

रितेश कुमार उर्फ विकास कुमार उर्फ विकास उर्फ रितेश, पुरुष, उम्र लगभग 24 साल, पिता मुकेश कुमार, निवासी गाँव -चंडी, पी. एस.-अरियारी, जिला-शेखपुरा।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी/ओं

उपस्थितिः

(आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 822/2021 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
		श्री बीरेंद्र कुमार अधिवक्ता
सूचनाकर्ता के अधिवक्ता	:	श्री गौरव प्रकाश, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	सुश्री शशि बाला वर्मा, एपीपी

(आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 99/2022 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री कौशल कुमार, अधिवक्ता
सूचनाकर्ता की ओर से	:	श्री गौरव प्रकाश, अधिवक्ता
राज्य/ओं की ओर से	:	सुश्री शशि बाला वर्मा, एपीपी

==========

अधिनियम/धारा/नियम:

- भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 302, 120 बी, 364 ए
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी

संदर्भित मामले:

- विक्रम सिंह एवं अन्य बनाम. पंजाब राज्य, 2010 में रिपोर्ट किया गया सभी एमआर (सीआरआई) 982 (एससी)
- शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116

- दिलावर हुसैन एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (1991) 1 एससीसी 253
- देवीलाल बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 2019 SC 688
- शिवाजी साहेबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1974 एससीआर (1) 489
- जसबीर सिंह बनाम. पंजाब राज्य की रिपोर्ट एआईआर 1998 SC 1660 में दी गई
- राजस्थान राज्य बनाम. गुरमेल सिंह ने एआईआर 2005 SC 1578 में रिपोर्ट दी
- पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एआईआर 1990 एससी 79
- जहरलाल दास बनाम. उड़ीसा राज्य की रिपोर्ट (1991) 3 एससीसी 27 में
- अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल और अन्य [2020] 7 एससीआर 180
- अनवर पी.वी. वी. पी.के. बशीर [2014] 11 एस.सी.आर. 399
- सुब्रमण्यम बनाम कर्नाटक राज्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1400
- आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह एवं अन्य एआईआर 2019 एससी 546

अपील- दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 ए, 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

निर्णय-मुकदमे में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था - अपीलकर्ताओं के नाम प्राथमिकी (एफ आई आर) में दर्ज नहीं थे-जांच रिपोर्ट गवाहों की उपस्थिति में तैयार की गई, लेकिन ये गवाह स्थानीय निवासी नहीं थे-अभियोजन पक्ष ने उन गवाहों से जिरह नहीं की, जिनकी उपस्थिति में जांच रिपोर्ट बनाई गई थी। (पैरा 39)

निचली अदालत ने कथित हथियार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं जताई - पीड़ित के शव के पास से बरामद काले तार पर मिले फिंगरप्रिंट को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। (पैरा 40)

निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के समस्त साक्ष्यों का रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के व्यापक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण नहीं किया - अभियोजन गवाहों की गवाही से यह स्पष्ट है कि साक्ष्यों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, झूठे फंसाने की प्रवृत्ति देखी गई और मात्र संदेह के आधार पर व्यक्तियों के नाम जोड़े गए। (पैरा 42)

इस मामले में केवल संदेह के आधार पर अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया - जिस फोन से फिरौती की कथित कॉल की गई थी, उसके स्वामी की गवाही नहीं हुई - यह

साबित करने के लिए कोई आवाज़ रिकॉर्डिंग प्रस्तुत नहीं की गई कि फिरौती की मांग वास्तव में अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा की गई थी। (पैरा 45)

अभियोजन पक्ष धारा 65 बी(5) के अनुपालन में रिपोर्ट को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे प्रस्तुत करने में विफल रहा। (पैरा 50)

जाँच अधिकारी ने अभियुक्त/अपीलकर्ता के इकबालिया बयान को दर्ज करने वाले दिन ही मृतक/पीड़ित का शव बरामद नहीं किया, बल्कि शव को 16 घंटे बाद बरामद किया-रिकॉर्ड में कोई गिरफ्तारी मेमो उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की तिथि व समय प्रमाणित हो सके। (पैरा 51)

जब अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं का इकबालिया बयान दर्ज किया जा रहा था, तब जाँच अधिकारी ने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बुलाया-अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा दिया गया कथित इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। (पैरा 53)

अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा कि मृतक का शव बरामद होने से पहले अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया गया था। (पैरा 54)

अपील स्वीकृत की जाती है। (पैरा 59)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

दिनांक: 16-01-2025

श्री अजय कुमार ठाकुर विद्वान, सीआर अपील (खं.पी.) संख्या 822/2021 में अपीलकर्ता के वकील, श्री बीरेंद्र कुमार, श्री कौशल कुमार, सीआर अपील (खं.पी.) संख्या

99/2022 में अपीलकर्ता के वकील, श्री गौरव प्रकाश, सूचनाकर्ता के वकील और सुश्री शशि बाला वर्मा राज्य के लिए एपीपी द्वारा सहायता प्राप्त।

2. दोनों अपीलें 2015 के बिहार थाना मामले संख्या 457 से उत्पन्न 2016 के सत्र वाद संख्या 337 में बिहार शरीफ में (इसके बाद 'विद्वत विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, नालंदा द्वारा पारित दिनांक 03.11.2021 (इसके बाद 'आक्षेपित निर्णय' के रूप में संदर्भित) और दिनांकित 20.11.2021(इसके बाद 'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित) सजा के आदेश से उत्पन्न हो रही हैं। विवादित निर्णय द्वारा, अपीलकर्ता, विवेक कुमार उर्फ विवेक उर्फ मोदी उर्फ राम विवेक कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120 बी (इसके बाद 'भा.दं.सं' के रूप में संदर्भित) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और 25000 रुपये के जुर्माने से गुजरने का दोषी ठहराया गया है। 25,000 रुपये जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त जुर्माने की राशि में से मृतक की मां को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। भा.दं.सं. की धारा 364 ए/120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। 25,000 जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त जुर्माने की राशि में से मृतक की मां को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। भा.दं.सं की धारा 201/120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए, उसे 7 वर्ष सश्रम कारावास से गुजरना पड़ेगा और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है और जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे और 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त जुर्माने की राशि में, रु7,000 मृतक की मां को भुगतान किया जाएगा। अपीलकर्ता रितेश कुमार उर्फ विकास कुमार उर्फ विकास उर्फ रितेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120 बी (इसके बाद 'भा.दं.सं' के रूप में संदर्भित) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने का दोषी ठहराया गया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे और 3 महीने का अतिरिक्त कारावास

भुगतना होगा। उक्त जुर्माने की राशि में, मृतक की मां को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। भा.दं.सं. की धारा 364 ए/120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त जुर्माने की राशि में से मृतक की मां को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। भा.दं.सं. की धारा 201/120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए, उसे सात साल के लिए कठोर कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे और 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त जुर्माने की राशि में, से मृतक की मां को 7,000 का भुगतान किया जाएगा।

<u>अभियोजन पक्ष का मामला</u>

3. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, सूचना देने वाले पीडब्लू-5 के *फर्दबयान* को अपराह्न 4 बजे 01.10.2015 को बिहार थाना कांड संख्या 457/2015 के पीएसआई जितेंद्र कुमार द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे रवि कुमार, उम्र 14 वर्ष, सुबह लगभग 7: 30 बजे कैम्ब्रिज स्कूल, प्रोफेसर कॉलोनी में पढ़ने के लिए घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आए। जब वह स्कूल गई और हेडमास्टर से उसके बेटे के ठिकाने के बारे में पूछा, तो उसे बताया गया कि लड़का स्कूल नहीं आया है। पड़ोस के इलाके में नाबालिग लड़के की तलाश करने के प्रयास किए गए। उसने रिश्तेदारों को भी बुलाया और पूछा लेकिन लड़का नहीं मिला। उनके सभी प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला। उसे संदेह था कि 28.09.2015 पर जब उसका बेटा रवि और बेटी अनन्या एटीएम से पैसे निकालने जा रहे थे, तो देवानंद ने उसके बेटे के साथ लड़ाई की और उसे धमकी दी। इसके अलावा, लगभग 20 दिन पहले, दो लोग उसके बहनोई राजीव कुमार शर्मा पर दो व्यक्तियों को विदेश भेजने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन उसके पति ने किसी को भी विदेश भेजने में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास वीजा नहीं था।

उसका साला पहले से ही उन लोगों से पैसे ले चुका था और उसके पति को धमकी दे रहा था कि लोगों को विदेश नहीं भेजने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अंत में, सूचक ने कहा कि उसे संदेह था कि उसके बेटे रवि कुमार का राजीव कुमार शर्मा और देवानंद ने कुछ अन्य लोगों के साथ अपहरण कर लिया था और वे मोबाइल नंबर 7321072463 से पैसे की मांग कर रहे हैं।

4. सूचक की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच अधिकारी बिहार थाना पुलिस ने थाना कांड संख्या 457/2015 के तहत धारा 364 ए, 363, 368, 302, 201 और 120 बी भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज कर लिया और दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। आठ सदस्यीय दल का गठन किया गया। सूचक ने फिरौती की मांग के बारे में तुरंत बिहार पुलिस स्टेशन की पुलिस को टेलीफोन नंबरों का विवरण दिया। जाँच अधिकारी ने सूचक और पीड़ित रवि कुमार से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए। बिहार पुलिस थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आई और एक आरोपी को जांच के लिए उठाया।

5. हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी विवेक कुमार उर्फ मोदी ने अपराध के बारे में कबूल किया और कहा कि वह अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों विकास कुमार उर्फ माली, सूरज कुमार, रितेश कुमार, मुन्ना कुमार के साथ पीड़ित रवि कुमार का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी। जाँच अधिकारी ने जाँच के लिए अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को भी अन्य स्थानों से गिरफ्तार किया। जाँच अधिकारी ने उस स्थान से शव और डेढ़ मीटर लंबा काले रंग का तार बरामद किया जहाँ लड़के का शव मिला था। यह स्थान अभियुक्त व्यक्तियों के कहने पर दिखाया गया था, जिन्होंने स्वेच्छा से वह स्थान दिखाया जहाँ उन्होंने पीड़ित रवि कुमार के शव को ठिकाने लगाया था आरोपियों ने पुलिस को 05.10.2015 को सुबह करीब 3:30 बजे एनएच-31 के पास स्थित घटनास्थल पर पहुंचाया, जो सड़क से 20 मीटर दूर चक्रसालपुर गांव के आसपास था। मृत शरीर की

पहचान की गई जिसे सूखे पत्तों और पेड़ की शाखाओं से ढककर रखा गया था और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने पीड़ित रवि कुमार के शव को कब्जे में लिया, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बिहार शरीफ के सदर अस्पताल, नालंदा भेज दिया। संबंधित डॉक्टरों ने पोस्टमॉर्टम किया और कहा कि पीड़ित रवि कुमार ने 36 से 72 घंटे पहले अंतिम सांस ली।

6. जाँच के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के इकबालिया बयानों से पता चलता है कि वे पीड़ित रवि कुमार के अपहरण के मिशन में शामिल थे। बयान के अवलोकन से यह भी पता चला कि सूरज कुमार ने पीड़ित रवि कुमार को मोटरसाइकिल पर इस बहाने उठाया कि वह उसे डिज्नी-लैंड ले जाएगा।

7. एक अन्य आरोपी उसके साथ पिलियन राइडर के रूप में शामिल हो गया और नाबालिग लड़के के साथ मौके से गायब हो गया। जाँच अधिकारी ने उन विभिन्न स्थानों का भी दौरा किया है जहाँ टावर लोकेशन पाया गया है। पहले उसने एस. पी., नालंदा के कार्यालय से सी. डी. आर. एकत्र किया और फिर जांच अधिकारी ने वह तार भी बरामद किया जिससे पीड़ित की हत्या का आरोप लगाया गया था। शव की बरामदगी से लेकर घटना तक की पूरी प्रक्रिया जो हुआ वह वीडियो-ग्राफ किया गया था और गवाह के सामने बरामद किया गया था। जाँच के दौरान विवेक उर्फ मोदी के मेडिकल हॉल से बरामद मोबाइल सेटों की जब्ती सूची भी तैयार की गई थी। जाँच पूरा होने के बाद, जाँच अधिकारी ने आठ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 364(ए), 363, 368, 302, 201 के साथ-साथ 120 बी के तहत आरोप पत्र विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कानून के दायरे में मुकदमे के लिए संबंधित किशोर न्याय बोर्ड, बिहार शरीफ नालंदा के समक्ष विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ एक अलग आरोप पत्र भी दायर किया।

8. भा.दं.सं. की धारा 364 ए, 363, 368, 302, 201 के साथ पठित 120 बी के तहत आरोप पत्र और आ.दं.सं. की धारा 173 के तहत जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का सत्यापन किया। यह पता चला कि आपराधिक साजिश के बाद फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। विद्वान दंडाधिकारी, बिहार शरीफ, नालंदा ने बिहार थाना कांड संख्या 457/2015 के मामले को जीआर 3903/2015 के संबंध में सत्र न्यायालय, नालंदा को अभियुक्तों के खिलाफ कानून के दायरे में विचारण के लिए दिनांक 15.06.2016 के प्रतिबद्धता आदेश के तहत भेजा है।

9. अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रकृति और अभियोजन पक्ष की ओर से पोषित आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत ने अभियुक्तों का बयान दर्ज किया ताकि उन्हें उनके खिलाफ अभिलेख पर लाई गई आपत्तिजनक परिस्थितियों को समझाने का अवसर दिया जा सके। लेकिन अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने जवाब में दोषपूर्ण परिस्थितियों का मुखरता से विरोध किया और आरोपों से इनकार किया। अभियुक्त व्यक्ति मामले में अपने झूठे निहितार्थ का दावा करते हैं। बचाव पक्ष ने कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि कुछ दस्तावेजी साक्ष्य दायर किए हैं।

<u>अभियोजन साक्ष्यों का विश्लेषण</u>

10. अभियोजन पक्ष की ओर से, कुल मिलाकर बारह गवाहों से पूछताछ की गई और मुकदमे के दौरान सोलह दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया जिन्हें यहाँ-नीचे सारणीबद्ध रूप में दिखाया जा रहा हैः

पीडब्लू-1	संजय कुमार
पीडब्लू-2	चंद्र भूषण प्रसाद
पीडब्लू-3	सुनील कुमार राजबंशी
पीडब्लू-4	विमला देवी
पीडब्लू-5	प्रीति देवी (पीड़ित की सूचना देने वाली माँ)
पीडब्लू-6	कामदेव शर्मा
पीडब्लू-7	सुनील कुमार निर्झर (जांच अधिकारी)
पीडब्लू-8	डॉ. अनूप कुमार
पीडब्लू-9	राकेश कुमार (जांच अधिकारी)
पीडब्लू-10	डॉ. फैसल अरशद (चिकित्सा अधिकारी)
पीडब्लू-11	जितेंद्र कुमार (जांच अधिकारी)

पीडब्लू-12	मो. जावेद अख्तर (नोडल अधिकारी भारती एयरटेल लिमिटेड, पटना)

<u>प्रदर्शों की सूची</u>

प्रदर्श-1	सूचना देने वाली प्रीति देवी के हस्ताक्षर
प्रदर्श-2	नितीश कुमार का लेखन और हस्ताक्षर

प्रदर्श-2/1	अपने ही इकबालिया बयान पर नितीश कुमार के अतिरिक्त हस्ताक्षर
प्रदर्श-3	सुनील कुमार के इकबालिया बयान और हस्ताक्षर पर विकास कुमार का लेखन और हस्ताक्षर
प्रदर्श-3/1	विकास कुमार उर्फ माली के हस्ताक्षर
प्रदर्श-3/2	रितेश कुमार का लेखन और हस्ताक्षर
प्रदर्श-4	इकबालिया बयान पर रितेश कुमार के हस्ताक्षर
प्रदर्श-5	इकबालिया बयान पर सूरज कुमार का लेखन और हस्ताक्षर
प्रदर्श-5/1	इकबालिया बयान पर सूरज कुमार के अतिरिक्त हस्ताक्षर
प्रदर्श-5/2	अर्णव कुमार के इकबालिया बयान पर राकेश कुमार का लेखन और हस्ताक्षर
प्रदर्श-6	इकबालिया बयान पर अर्णव कुमार के हस्ताक्षर
प्रदर्श-7	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
प्रदर्श-8	विवेक कुमार उर्फ मोदी का इकबालिया बयान
प्रदर्श-9	पत्र संख्या 236/2016 के माध्यम से एस. पी. का पत्र
प्रदर्श-10	प्रपात्रा IV

प्रदर्श-11	सी. डी. आर.
प्रदर्श-12	मोबाइल सेटों की बरामदगी सूची

प्रदर्श-13	मोटरसाइकिल की ज़ब्त सूची
प्रदर्श-14	प्रभार पत्रक संख्या 448/2015
प्रदर्श-15	सी. ए. एफ. (आपत्ति के साथ)
प्रदर्श-16	पूछताछ रिपोर्ट
	जाँच रिपोर्ट पर रामदेव शर्मा के हस्ताक्षर
प्रदर्श-17	जाँच रिपोर्ट पर गणेश शर्मा के हस्ताक्षर

बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य

प्रदर्श-ए	अतिरिक्त-विमला देवी का बयान (2015 का जेजेबी मामला संख्या 191 देखें)
प्रदर्श-ए/1	प्रीति देवी का बयान
प्रदर्श-ए/2	अर्चना शर्मा का बयान
प्रदर्श-ए/3	कामदेव शर्मा का बयान
प्रदर्श-ए/4	चंद्र भूषण प्रसाद का बयान
प्रदर्श-ए/5	किशोरी प्रसाद का बयान
प्रदर्श-ए/6	जितेंद्र कुमार का बयान
प्रदर्श-ए/बी	2015 के जेजेबी मामले संख्या 191 के निर्णय

	की प्रमाणित प्रति

11. अभियोजन पक्ष की कहानी सूचनादाता, पीडब्लू-5 पीड़ित की माँ द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि 01.10.2015 पर, उसका बेटा 7:30 बजे स्कूल के लिए रवाना हुआ प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ने के लिए आया और वापस नहीं आया। जब वह स्कूल जा रहा था, सूरज कुमार नाम का एक लड़का गेट पर खड़ा था जो इलाके में किराए पर रहता था। उसी दिन 12:27 बजे उन्हें एक फोन आया जिसमें बताया गया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और उन्होंने 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है, अन्यथा उसके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद, वह पहले स्कूल गई, जहाँ उसने हेडमास्टर से अपने बेटे के बारे में पूछा। पता चला कि उसका बेटा स्कूल नहीं आया था। 12:31 शाम को उसका फोन एक बार फिर बजने लगा। इसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों और दुबई में काम करने वाले अपने पति को बुलाया। अपहरण के समय बेटा 14 साल का था। जब वह नहीं आया तो उसने पुलिस स्टेशन को लिखित शिकायत दी और दोनों फोन नंबरों के बारे में बताया जिससे उसे कॉल आए और इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। अपनी प्राथमिकी में, पीडब्लू-5 ने दो व्यक्तियों, देवानंद और राजीव कुमार शर्मा को इस संदेह के आधार पर नामित किया कि उन्होंने उसके बेटे का अपहरण किया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान वे निर्दोष पाए गए। घटना के 4 दिन बाद उसके बेटे का शव बरामद किया गया।उसने अस्पताल में शव देखा।

11.i. अपनी जिरह में, उसने कहा कि उसने जो कुछ भी प्राथमिकी में लिखा था वह केवल संदेह के आधार पर था, क्योंकि 20 दिन पहले उसके पति का राजीव कुमार शर्मा के साथ झगड़ा हुआ था और कुछ दिन पहले उसके बेटे और देवानंद के बीच कुछ

झगड़ा हुआ था जब वह एटीएम से पैसे निकालने जा रहा था। वह किसी भी आरोपी को नहीं जानती थी और आरोपी सूरज, जो उसका पड़ोसी था, ने जो बताया था, उसके आधार पर उसने आरोपी का नाम लिया। उसने कहा कि उसने 04.10.2015 को अस्पताल में अपने बेटे का शव देखा था।

12. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 नाम के संजीव कुमार और चंद्र भूषण प्रसाद सिंह भाई थे और हिमगंगे जल संयंत्र के संयुक्त मालिक थे, जहाँ कथित तौर पर अपहृत बच्चे को रखा गया था। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 दोनों ने अपने जाँच प्रमुख में कहा है कि उन्हें घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे केवल एक आरोपी रितेश को जानते थे जो उनके जल संयंत्र में काम करता था।

13. पीडब्लू-3 सुनील कुमार राजवंशी को बिहार पुलिस स्टेशन में उप-निरीक्षक के रूप में 01.10.2015 पर तैनात किया गया था और उन्होंने अपने मुख्य जाँच अधिकारी को बताया कि घटना की तारीख को उन्हें प्रातः 7:30 बजे पंडित नगर से एक लड़के के अपहरण की जानकारी मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस थाने के एस. एच. ओ. ने एक जांच दल का गठन किया जिसमें उप-निरीक्षक अनूप कुमार, उप-निरीक्षक राकेश कुमार, उप-निरीक्षक जितेंद्र कुमार, उप-निरीक्षक सुनील कुमार निर्झर और जिला सूचना इकाई के उप-निरीक्षक आलोक कुमार शामिल थे। उसी दिन अपराह्न 12:27 पर, सूचक को एक फोन आया जिसमें उसे बताया गया कि उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया है, जिसके बाद उसने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। पीडब्लू-3 ने कहा कि उन्होंने कॉल विवरण और मोबाइल के स्थान को ट्रैक किया जिससे पता चला कि कॉल नालंदा जिले के कई स्थानों से की गई थी। जांच में यह पाया गया कि जिस कथित मोबाइल नंबर से फिरौती की मांग की गई थी, वह संजीव कुमार, पुत्र मेवालाल राय का था, जो पटना में रहता था। संजीव कुमार ने पुलिस को सूचित किया कि वह लंबे समय से बिहार शरीफ नहीं गया था और उसे बिहार

शरीफ से कोई मोबाइल नंबर नहीं मिला था। आगे की जाँच में, यह पाया गया कि जिस दुकान से नंबर लिया गया था, वह बिहार पुलिस स्टेशन के तहत बिनौलिया में स्थित विवेक मेडिकल हॉल था। उसके बाद मेडिकल स्टोर से संपर्क किया गया और पूछताछ की गई, जहां से यह बताया गया कि बिनौलिया में किराए के मकान में रहने वाले अर्णव नाम के एक लड़के को विशेष सिम दिया गया है। फिर पुलिस अर्णव से पूछताछ करने के लिए किराए के घर गई, लेकिन वह फरार पाया गया।

13.i.इसके अलावा, पुलिस ने मेडिकल हॉल की तलाशी ली और उस जगह से कई नकली सिम बरामद किए गए। मेडिकल हॉल के मालिक, अपीलकर्ताओं में से एक विवेक कुमार उर्फ मोदी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसने अपने इकबालिया बयान में कहा कि 2 महीने पहले विकास कुमार माली, सूरज कुमार, रितेश कुमार, मुन्ना कुमार और उसने खुद बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के पास किसी का अपहरण करने की योजना बनाई थी। मुन्ना कुमार ने कहा कि वह हथियार की व्यवस्था करेगा। नितीश कुमार ने कहा कि वह वाहन की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद अपीलकर्ता ने खुद कहा कि वह फर्जी सिम का इंतजाम करेगा। विकास उर्फ माली ने कहा कि वे दोनों पीड़ित को रखने की व्यवस्था करेंगे। तब सूरज कुमार ने कहा कि वह एक लड़के को जानता है जो बहुत अमीर था और उसके पिता विदेश में रहते थे। योजना के अनुसार, 01.10.2015 पर, रवि कुमार 7:30 बजे स्कूल के लिए घर से निकले इस बीच रास्ते में सूरज कुमार और रोहित कुमार दोनों ने लड़के को मोटरसाइकिल पर बिठाया क्योंकि सूरज कुमार उस लड़के को अच्छी तरह से जानता था। वह बगल में किराए पर रहता था। उसके बाद, रवि कुमार को डिज्नीलैंड दिखाने के बहाने, वह उन्हें डिज्नीलैंड के पास हिमगंगे जल संयंत्र के कमरे में ले गया। विवेक कुमार उर्फ मोदी, विकास उर्फ माली, मुन्ना कुमार, रितेश कुमार, नितीश कुमार पहले से ही उस कमरे में थे। वह कमरा रितेश कुमार का था जो हिमगंगे जल संयंत्र में काम करता था। लड़के का अपहरण करने के बाद आरोपी ने विभिन्न स्थानों से सूचक से पैसे की

मांग की। उनमें से कुछ लोग पुलिस की गतिविधि को भी देख रहे थे क्योंकि उन्हें लगने लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। फिर 02.10.2015 और 03.10.2015 पर, मृतक रवि को दीपनगर चक्रसालपुर एनएच-31 ले जाया गया और कथित तौर पर वहाँ उसकी हत्या कर दी गई। शव को एनएच-31 के पास झाड़ी में फेंक दिया गया था। उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। रवि कुमार का शव 04.10.2015 पर बरामद किया गया था। जिस तार से मृतक का कथित तौर पर गला घोंटा गया था, वह भी शव के पास से बरामद किया गया था। शव की बरामदगी से लेकर पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई तथा शव की खोज गवाहों के समक्ष की गई।

13.ii.अपनी जिरह में, पीडब्लू-3 ने कहा कि जाँच रिपोर्ट में, शव की खोज के स्थान का अस्पष्ट उल्लेख था। खोज के विशिष्ट स्थान का उल्लेख नहीं किया गया था।

14. पीडब्लू-4 विमला देवी मृतक पीड़िता की चाची हैं। उसने अपने मुख्य जाँच में कहा कि उसने सूरज और विकास उर्फ रितेश को छोड़कर किसी भी आरोपी को नहीं पहचाना। उसने आगे कहा कि चूंकि अभियुक्तों को फिरौती की राशि नहीं दी गई थी, इसलिए उन्होंने उसके भतीजे, पीड़ित को उसके मुंह में कपड़े का टुकड़ा डालकर और बिजली के तार से गला घोंटकर मार डाला।

14.i.अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा कि उसे घटना की जानकारी तब मिली जब वह एरिना में थी। वह पीडब्लू-5 प्रीति देवी से मिलने बिहार शरीफ गई, जिन्होंने उन्हें घटना के बारे में बताया। बाद में उसने कहा कि उसे घटना की जानकारी उसके भाई कामदेव शर्मा यानी पीडब्लू-6 से मिली थी।

15. पीडब्लू-6 कामदेव शर्मा मृतक के पिता हैं। घटना के दिन वह दुबई में था, जहाँ वह काम करता था। अपने मुख्य परीक्षण में उसने बताया कि 01.10.2015 को दोपहर 12 बजे उसकी पत्नी ने उसे बताया कि सुबह सूरज कुमार उनके बेटे को लेने आया

था और उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। उसने यह भी कहा कि अभियुक्तों ने उसे फोन किया था और 70 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी, ऐसा न करने पर वे अपने बेटे की हत्या कर देंगे। वह दुबई से 03.10.2015 पर वापस आया। उनके बेटे का शव एनएच-31 पर सड़क के पास से बरामद किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वह केवल सूरज और विवेक को पहचानते थे जो उनके घर आते रहते थे। अपनी जिरह में पीडब्लू-6 ने कहा है कि उसे अपनी पत्नी और पड़ोसियों से घटना की जानकारी मिली थी।

16. पीडब्लू-7 सुनील कुमार निर्झर ने अपने मुख्य जाँच में कहा कि घटना की तारीख को उन्हें बिहार पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात किया गया था। पीड़ित रवि कुमार की खोज और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया था। टीम में एसएचओ बिहार राजेश कुमार शर्मा, सुनील कुमार राजवंशी, अनूप कुमार, जितेंद्र कुमार, राकेश कुमार और आलोक कुमार शामिल थे। विवेक कुमार उर्फ मोदी ने पूरी घटना के बारे में अपना इकबालिया बयान दिया और विकास कुमार, अर्णव कुमार, मुन्ना कुमार, रितेश कुमार, सूरज कुमार और नितीश कुमार को सह-आरोपी के रूप में नामित किया। उसने कबूल किया कि सूरज कुमार ने उन्हें बताया कि अपहृत बच्चे का पिता एक अमीर आदमी था जो विदेश में काम करता था। अभियुक्तों में से एक, मुन्ना कुमार अपराध के हथियार की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गए, नितीश कुमार ने वाहन की व्यवस्था की। विकास कुमार ने पीड़ित को एक स्थान पर बंधक रखने की व्यवस्था की। विवेक कुमार ने एक झूठी आईडी की व्यवस्था की जिसके आधार पर कथित सिम कार्ड लिया गया था जिसका उपयोग फिरौती कॉल करने के लिए किया जाना था। अपनी साजिश के अनुसार, 01.10.2015 की सुबह सूरज कुमार और नितीश कुमार मृतक पीड़ित रवि कुमार को डिज्नीलैंड जाने के बहाने ले गए और उसे हिमगंगे जल संयंत्र के एक कमरे में बंद कर दिया।वहाँ रवि कुमार को हाथ-पैर बांधकर रखा गया था। 70 लाख रुपये की फिरौती मांगी

गई और पैसे नहीं मिलने पर रवि कुमार की हत्या कर दी गई और शव को एनएच-31 पर एक झाड़ी में फेंक दिया गया।

16.i. सूचक को उसके मोबाइल नंबर-95045439203 पर 7321072463 और 8873094952 से फिरौती की मांग करते हुए दो कॉल आए। सभी अपराधियों के मोबाइल टावर क्रमशः अरावत, बेना पुलिस स्टेशन, मुसहरी, रूपसपुर, मेहनौर, होस्टतुंगी, थाना दीपनगर, पटेल नगर, नई सराय, अज़ीज़ घाट, बिहार शरीफ, शेखाना और बिनौलिया में पाए गए। सिम संजीव कुमार, गाँव मोहल्ला उत्तर मंदिर पटना के नाम से जारी किया गया था। सत्यापन पर, यह पाया गया कि सिम कार्ड विवेक मेडिकल हॉल, बनौलिया पुलिस स्टेशन, बिहार द्वारा जारी किया गया है। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ पर विवेक कुमार उर्फ मोदी ने कहा कि उसने अर्णव कुमार को सिम कार्ड दिया था। दोनों नंबरों का मोबाइल टावर बिहार शरीफ के पास भी पाया गया। दिनांक 4.10.2015 पर सिम कार्ड विक्रेता विवेक कुमार उर्फ मोदी की दुकान की तलाशी ली गई और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और 9 मोबाइल बरामद किए गए।

16.ii.अभियुक्त-अपीलार्थी के इकबालिया बयान के आधार पर शव बरामद किया गया और शव के पास से एक काला तार बरामद किया गया और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई। पीडब्लू-7 ने आगे कहा कि उसने 4.10.2015 पर एक आरोपी नितीश कुमार का इकबालिया बयान दर्ज किया, जिसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। दिनांक 4.10.2015 पर ही, रात्रि 11:30, विकास कुमार उर्फ माली के इकबालिया बयान को भी उन्होंने लिया और लिखित रूप में कलमबद्ध कर दिया।

16.iii.अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-7 ने कहा कि अपहृत पीड़ित की खोज के लिए केवल एक टीम का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। उसे पता नहीं था कि जिस व्यक्ति के नाम पर सिम जारी

किया गया था, उसे गिरफ्तार किया गया था या नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने खोज के स्थान पर काले तार को देखा, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या यह आपत्तिजनक सामग्री निचली अदालत के समक्ष पेश की गई थी। उन्हें यह भी पता नहीं था कि क्या तार को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि जिस स्थान से शव मिला था, वह कोई अलग जगह नहीं थी। 100-200 मीटर की दूरी पर घर थे।

16.iv.उन्होंने आगे कहा कि जिस दुकान से सिम लिया गया था, उसके मालिक को पुलिस को घटना की सूचना दिए जाने के दो दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस बात का कोई कागजी सबूत नहीं था कि नितीश कुमार और विकास कुमार हिमगंगे जल संयंत्र में रहते थे, लेकिन उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि सिम विक्रेता की दुकान से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे, लेकिन उन्होंने यह याद होने से इनकार किया कि सामान जब्त किए गए थे या नहीं। गवाह ने इन सुझावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया कि आरोपी का इकबालिया बयान नहीं लिया गया था, लेकिन उसने स्कूल जाने वाले छात्रों को गिरफ्तार कर लिया था, और नितीश और विकास हिमगंगे जल संयंत्र में काम नहीं करते हैं, लेकिन वे इंटरमीडिएट के छात्र हैं। गवाह ने आगे कहा कि संजीव कुमार के बयान और तकनीकी कारणों से विवेक की दुकान पर छापा मारा गया था, विवेक की खिचडी परोसे की दुकान थी जिसमें वह सिम आदि भी बेचता था। विवेक की दुकान पर छापेमारी में कुछ सिम मिले, उसे याद नहीं था कि वहां कितनी चीजें मिली थीं, जब्ती की सूची बनाई गई थी। बरामद किए गए सभी मोबाइल पुराने थे।

17. पीडब्लू-8 अनूप कुमार ने अपने जाँच प्रमुख में कहा कि 04.10.2015 पर उन्हें बिहार पुलिस स्टेशन में उप-निरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था। उक्त तिथि को अपहृत रवि कुमार की तलाश और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई थी। टीम में एसएचओ बिहार राजेश कुमार शर्मा, सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार राजवंशी, सब-

इंस्पेक्टर सुनील कुमार निर्झर, सब-इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार (जांच अधिकारी) और जिला खुफिया इकाई के सब-इंस्पेक्टर आलोक कुमार शामिल थे। उन्होंने कहा कि जांच दल को जांच करने के लिए दो समूहों में विभाजित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने हिमगंगे जल संयंत्र के आसपास की जगह की तलाशी ली, जहां उन्होंने एक आरोपी रितेश कुमार से पूछताछ की। अभियुक्तों ने शुरू में उनके साथ सहयोग नहीं किया, लेकिन फिर स्वीकार किया कि अपहृत पीड़ित रवि कुमार का अपहरण उसके पिता से फिरौती मांगने के उद्देश्य से किया गया था और विकास कुमार उर्फ माली, अर्णव कुमार, मुन्ना कुमार, विवेक कुमार उर्फ मोदी, सूरज कुमार और नितीश कुमार साजिश में शामिल थे।

17.i पीडब्लू-8 ने आगे कहा कि अपीलकर्ता रितेश ने स्वीकार किया कि फिरौती की राशि प्राप्त करने पर, वह और सह-आरोपी रवि कुमार को एनएच-31 चक्रमसलपुर पर एक जगह पर ले गए जो धर्मेंद्र की सीमेंट की दुकान से 50 मीटर दूर था और वहां उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एनएच-31 पर एक झाड़ी में छिपा दिया। रितेश का इकबालिया बयान खुद पीडब्लू-8 ने दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि पुलिस की दूसरी टीम चार अपहरणकर्ताओं के साथ जल संयंत्र पहुंची। इसके बाद गिरफ्तार आरोपियों के साथ पूरी टीम आरोपी रोहित कुमार के गांव पटुआना में उसके घर गई और उसके घर की तलाशी ली और उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम गांव गौरागढ़ गई और सूरज कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।वहाँ से टीम और सभी आरोपी एन-31 चक्रमसलपुर गए जहाँ से पीड़ित रवि कुमार का शव मिला। उन्हें लगभग डेढ़ मीटर लंबा एक काला प्लास्टिक का तार मिला जिसका उपयोग कथित तौर पर रवि कुमार को मारने के लिए गला घोंटने के लिए किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई और मामले के जांच अधिकारी यानी पीडब्लू-11 द्वारा ब्लैक वायर को जब्त कर लिया गया।

17.ii.अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-8 ने कहा कि वह इस घटना के चश्मदीद नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि रितेश कुमार हिमगंगे जल संयंत्र में काम करते थे।उन्हें नहीं पता था कि तत्काल मामले में किसे आरोपी बनाया गया था।

18. पीडब्लू-9 राकेश कुमार ने अपने जाँच-प्रमुख में कहा कि 04.10.2015 पर उन्हें बिहार पुलिस स्टेशन में पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था। उसी दिन एक लड़के रवि कुमार का अपहरण कर लिया गया था और बिहार पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 457/15 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एक टीम का गठन किया गया था जिसमें जितेंद्र कुमार (जांच अधिकारी), सुनील कुमार राजवंशी, सुनील कुमार निर्झर, अनूप कुमार और आलोक कुमार टीम के सदस्य थे। टीम को दो भागों में बांटा गया था। सशस्त्र बलों के साथ उनकी और एस. आई. अनूप कुमार की एक टीम पश्चिम नाला रोड की ओर गई थी, और आई. ओ. जितेंद्र कुमार, एस. आई. सुनील कुमार राजवंशी, एस. आई. सुनील कुमार निर्झर और एस. आई. आलोक कुमार की दूसरी टीम को ठाणे से पूर्वी बनौलिया की ओर भेजा गया था।

18.i.नाला रोड पर स्थित न्यू सिटी फैमिली रेस्तरां के पास हिमगांज जल आपूर्ति संयंत्र के पास पहुंचने पर पीडब्लू-9 ने हिमगांज जल संयंत्र के एक कर्मचारी से मुलाकात की। कर्मचारी का नाम पूछने पर उसे बताया गया कि उसका नाम रितेश कुमार है और वह जल संयंत्र में काम करता है। बाद में, घटना के बारे में पूछे जाने पर, उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि वह संयंत्र में ही एक कमरे में रहता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि रवि कुमार को हाथ-पैर बांधकर वहाँ रखा गया था। रितेश कुमार का इकबालिया बयान एस. आई. अनूप कुमार ने लिया था जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। टीम खोज करने के लिए फतुआ गई जहां से रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसने

अपहरण की साजिश में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की। वहाँ से टीम सूरज कुमार के घर गई जिसे अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।सूरज कुमार का इकबालिया बयान इस गवाह द्वारा लिया गया है, जिसकी पहचान उसने अपने ही हस्ताक्षर से की है।

18.ii.गवाह ने आगे कहा कि आरोपी के कहने पर पूरी टीम आरोपी व्यक्तियों के साथ एन. एच.-31 पर स्थित गाँव चक रसूलपुर पहुंची, जहाँ दुर्गंध आ रही थी। पीड़ित रवि कुमार का शव सड़क के पश्चिम की ओर एक पेड़ के नीचे पेड़ के पत्तों से ढका हुआ पाया गया। शव के बगल में एक काले रंग का प्लास्टिक का तार मिला, जो लगभग डेढ़ मीटर लंबा था। जितेंद्र कुमार ने शव की जांच रिपोर्ट तैयार की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया गया। सभी पुलिस दल सदर अस्पताल बिहार शरीफ पहुंचे। अर्णव कुमार उर्फ शिवम कुमार का इकबालिया बयान भी पीडब्लू-9 ने लिया था।

19. पीडब्लू-10, डॉ. फैसल अरशद ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि 05.10.2015 पर उन्हें सदर अस्पताल, बिहार शरीफ, नालंदा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। इस दिन 9 साल की उम्र में लगभग 14 साल के रवि कुमार के शव का पोस्टमॉर्टम प्रात 9:10 बजे किया गया था जिसे हवलदार 84, हरि मोहन सिंह द्वारा लाया और पहचाना गया था। बाहरी जाँच में उन्होंने पाया कि चारों अंगों में शवकाठिन्य अनुपस्थित थी। शव सड़ने की अवस्था में था। दोनों हाथ सूती रस्सी से बंधे हुए थे। जगह-जगह फफोला पूरे शरीर पर और पूरा शरीर फूला हुआ था। दाहिनी आंख अपने साकेट से बाहर निकल गई। मैगॉट्स दोनों आँखों और पूरे चेहरे के अंदर रेंग रहे थे। पूरे शरीर से बदबू आ रही थी।

19.i.उन्होंने कहा कि मुंह को लंबे सूती कपड़े से बंद कर दिया गया था। गुदा छिद्र में एक लंबा सूती कपड़ा डाला गया था। लिगचर का निशान, काला रंग पूरी गर्दन को घेरता था और 3/4 इंच चौड़ा था।

विच्छेदन पर-सिर-मस्तिष्क में सभी कपाल की हड्डियाँ अक्षुण्ण थीं और इसके मेनिन्जेस अक्षुण्ण और रक्तसंकुल वाले थे।

गर्दन-बंधन ऊतक के निशान के नीचे संकुचित पाया गया।

ट्रेकिया-संपीड़ित और टूटा हुआ और संकुचित और ह्योइड हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया

वक्ष- वक्षीय पिंजरा एन. ए. डी

हृदय-सभी कक्ष गहरे रंग के खून से भरे हुए हैं।

फेफड़े-इंटैक्ट और संकुचित।

पेट-खाली है।

मूत्राशय-खाली।

अन्य सभी पेट के विसरा बरकरार और संकुचित हैं।

राय-मेरी राय में मृत्यु का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप दम घुटना है। मृत्यु के बाद से 36 से 72 घंटों के भीतर समय बीत गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कंप्यूटर पर उनके निर्देश पर तैयार की गई थी और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

19.ii.अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मृत्यु के एक घंटे बाद कठोर मृत्यु पैरों की उंगलियों से शुरू होती है और धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाती है।

यह 24 घंटे तक रहता है।यह गलत है कि 72 घंटे के लिए कठोर मृत्यु संभव है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि किस अंग से कठोर मृत्यु गायब होती है, हाथ की उंगलियों से या किसी अन्य अंग से गला घोंटने की स्थिति में हृदय के कक्ष भीड़-भाड़ वाले हो जाते हैं और काले रक्त से भर जाते हैं। चूंकि शरीर सड़ रहा था, इसलिए शरीर पर चोट का कोई बाहरी निशान नहीं मिला। कीड़े मृतक के शरीर को खा रहे थे। खाली पेट से पता चलता है कि मृतक ने लंबे समय से खाना नहीं खाया था। यदि शव को मैदान में खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है, तो शव को सड़ने के लिए कितना समय पर्याप्त होगा, यह समझ में नहीं आता है। शरीर पर काले बंधन के निशान दिखाई दिए और हर चोट काली हो गई। उन्होंने आगे कहा कि वह यह नहीं कह सकते कि चोट को भूरे रंग में बदलने में कितना समय लगेगा। चोट की उम्र का आकलन चोट के रंग से किया जाता है, हालांकि उन्होंने कहा हालांकि उन्होंने कहा कि यदि चोट का रंग काला हो गया है तो वे चोट की उम्र नहीं बता सकते।

20. पीडब्लू-11 जितेंद्र कुमार, तत्काल मामले में जाँच अधिकारी थे और उन्होंने अपने जाँच-इन-चीफ में कहा है कि 01.10.2015 पर उन्हें बिहार पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेक्टर के रूप में तैनात किया गया था, और 2015 के बिहार पुलिस स्टेशन केस नंबर 457 की जाँच का कार्यभार संभाला। उन्होंने सूचना देने वाले का लिखित आवेदन केस डायरी में दर्ज किया। इसके बाद उन्होंने फिर से मुखबिर का बयान लिया। घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने गवाह विमला देवी, अर्चना कुमारी का बयान लिया। इस घटना में इस्तेमाल किया गया कथित मोबाइल नंबर 7321072463 था। इसका सी. डी. आर. प्राप्त करने के लिए, पत्र संख्या 2724/15 के माध्यम से रिपोर्ट के लिए पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा गया था। उसने पुलिस अधीक्षक से अपहरण मामले में इस्तेमाल मोबाइल का सीडीआर और सीएएफ प्राप्त किया, जिसके माध्यम से पैसे की मांग की गई थी।

20.i.रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया गया कि उसका मोबाइल नंबर एयरटेल रिटेलर आईडी 8969057151 से खरीदा गया था जो विवेक कुमार का विवेक मेडिकल हॉल बनौलिया, बिहार शरीफ पुलिस स्टेशन, बिहार से था। उक्त सिम की खरीद में इस्तेमाल किया गया मतदाता पहचान पत्र, जिसका नंबर ए. एफ. 50178707 था, जो संजीव कुमार सिंह पुत्र मेवालाल राय, 71 उत्तरी मंदिर पटना, सर्कल पटना जिले का था। विवेक मेडिकल हॉल पहुंचने पर पता चला कि अपहरण में प्रयुक्त मोबाइल नंबर (7321072463) अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा घटना में फिरौती मांगने के लिए फर्जी तरीके से जारी किया गया था। उस मोबाइल नंबर के सी. डी. आर. और सी. ए. एफ. ने दिखाया कि 7321072463 और 9304445877 के बीच बातचीत हुई थी। यह मोबाइल नंबर मुन्ना कुमार पिता: राजू यादव, गढ़, बिहार शरीफ के नाम से जारी किया गया था, जिसने अपहरण और फिरौती मांगने के अपराध को अंजाम देने की प्रक्रिया में मुखबिर को फोन किया था। सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, एस. आई. अनूप कुमार, एस. आई. सुनील कुमार निर्झर, एस. आई. सुनील कुमार राजवंशी, उमेश कुमार और थाने के सशस्त्र बलों की एक टीम का गठन किया गया था।टीम को दो भागों में बांटा गया था।

20.ii.पीडब्लू-11 अपनी टीम के साथ बनौलिया के लिए रवाना हुआ और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने विवेक उर्फ मोदी की दुकान की तलाशी ली। वहाँ से विवेक उर्फ मोदी को गिरफ्तार किया गया और उसकी दुकान से 9 मोबाइल बरामद किए गए। विवेक उर्फ मोदी का इकबालिया बयान भी लिया गया था, जिसे प्राथमिकी के साथ जोड़ा गया था और अदालत में भेजा गया था। विवेक कुमार उर्फ मोदी का इकबालिया बयान पीडब्लू-11 द्वारा दर्ज किया गया था। टीम ने नितीश कुमार के घर की भी तलाशी ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से ही बीआर-21-सी-2049 पंजीकरण वाली मोटरसाइकिल बरामद की गई। नितीश कुमार का इकबालिया बयान लिया गया। बनौलिया से टीम गढ़पर बिहारशरीफ गई, जहां मुन्ना कुमार के घर की तलाशी ली और उसके बाद

उसे गिरफ्तार कर लिया। बनौलिया से टीम नाला रोड स्थित हिमगांगे आपूर्ति कार्यालय पहुंची, जहां दूसरी टीम पहले से ही मौजूद थी और पुलिस उपनिरीक्षक अनूप कुमार ने वहां से रितेश कुमार को गिरफ्तार किया और उसका इकबालिया बयान लिया। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उन्होंने पैसे की मांग करने के लिए रवि कुमार का अपहरण किया था और पैसे नहीं मिलने के बाद और पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से, उन्होंने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एन. एच. 31 चक्रसालपुर के पास फेंक दिया। टीम सभी अभियुक्त व्यक्तियों के साथ एन. एच. 31, रसालपुर की ओर बढ़ी और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि एन. एच.-31 से 20 मीटर पश्चिम में पेड़ की शाखाओं और सूखी पत्तियों से कुछ ढका हुआ था और शव से बदबू आ रही थी। पूरे शरीर पर फफोले पाए गए। अपहृत रवि कुमार का शव आरोपी के कहने पर घटनास्थल से बरामद किया गया, जांच रिपोर्ट तैयार की गई और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। शरीर के चेहरे पर सूजन, गर्दन में सूजन, दोनों आंखों में रेंगने वाले मैगॉट्स पाए गए, गले के चारों ओर एक काला धब्बा था, गर्दन में लगभग डेढ़ मीटर की दूरी पर एक काला प्लास्टिक का तार पाया गया और मौत का कारण गला घोंटना था।

20.iii दिनांक 09.10.2015 पर, कथित मोबाइल नंबरों के सी.डी.आर. एवं सी.ए.एफ. का उपयोग प्रयुक्त कथित मोबाइल नम्बर 7321072463 एवं 8873094952 का सी.डी.आर. एवं सी.ए.एफ. डी.आई.यू., पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नालंदा के पत्रांक 236/2019 के माध्यम से मांगा गया और दिनांक 03.11.2019 पर फॉर्म-IV के तहत जिला सूचना इकाई द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। जब रिपोर्टों की बारीकी से जांच की गई तो यह स्पष्ट हो गया कि फिरौती कॉल प्रीति देवी के मोबाइल नंबर 9504549203 पर 7321072463 और 8873094952 से फिरौती के रूप में 70,00,000 की राशि के लिए की गई थी। मोबाइल नंबर 7321072463 के सीएएफ के अवलोकन से

ऐसा प्रतीत होता है कि सिम संजीव कुमार सिंह के नाम से जारी किया गया था। विवेक कुमार के मेडिकल हॉल से सिम कार्ड खरीदने के लिए एएफ 150178707 नंबर वाले मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र में तस्वीर कंपनी से प्राप्त तस्वीर से अलग थी, जिसमें दिखाया गया था कि अपीलकर्ता-आरोपी विवेक कुमार उर्फ मोदी ने बिना सत्यापन के पीड़ित के अपहरण के लिए यह सिम कार्ड प्राप्त किया था। जब्ती सूची तैयार की गई थी जो पीडब्लू-11 की लिखावट में थी। दिनांक 14.10.2015 को, मृतक रवि कुमार की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई। पीडब्लू-11 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि सूचना देने वाले ने अपने बयान में कहा कि 28.09.2015 पर उसका बेटा और बेटी एटीएम से पैसे निकालने जा रहे थे, जहां उनकी देवानंद से लड़ाई हुई थी, जिसने उसे अपहरण करने की धमकी दी थी। उसने यह भी कहा कि 20 दिन पहले एक राजीव कुमार का उसके पति के साथ झगड़ा हुआ था। एफ. आई. आर. में अपीलकर्ता-अभियुक्तों का नाम नहीं था। पीडब्लू-4, विमला देवी और एक अर्चना कुमारी ने अपने बयान में यह भी कहा कि देवानंद नाम के एक लड़के ने रवि कुमार को अपहरण करने की धमकी दी थी और राजीव कुमार शर्मा ने भी धमकी दी थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने देवानंद या राजीव कुमार शर्मा के खिलाफ जांच नहीं की।

20.iv.उनकी जिरह के पैरा-15 में पीडब्लू-11 ने कहा कि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जिसने पीड़ित के अपहरण या हत्या की घटना को देखा हो। पैरा-16 में उन्होंने कहा कि शव के पास से मिले काले तार पर पाए गए उंगलियों के निशान की कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि मृतक के मुंह से कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। डॉक्टर ने शव के पोस्टमॉर्टम के बाद कपड़े का कोई टुकड़ा भी जमा नहीं किया। अपीलार्थी-अभियुक्त रितेश को 04.10.2015 पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 6.10.2015 तक दंडाधिकारी के सामने पेश नहीं किया गया था। इसके अलावा, जिस मोबाइल फोन का उपयोग कॉल करने के लिए किया गया था,

वह रितेश कुमार के नाम पर नहीं था। सिम के मालिक संजीव कुमार सिंह को वर्तमान मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 19 में उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह सत्यापित नहीं किया कि सूचना देने वाले को किसने कॉल किया और कोई वॉयस रिकॉर्डिंग नहीं मिली जिससे पता चले कि आरोपी ने कॉल किया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने दोनों आरोपियों के इकबालिया बयान को रिकॉर्ड नहीं किया।

21. पटना में भारती एयरटेल लिमिटेड के नोडल अधिकारी पीडब्लू-12 मोहम्मद जावेद अख्तर ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उन्होंने अदालत के समक्ष मोबाइल नंबर 7321072463 का मूल सीएएफ पेश किया। उन्होंने कहा कि सिम विवेक मेडिकल हॉल, बनौलिया, बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार के खुदरा विक्रेता द्वारा संजीव कुमार सिंह के नाम पर चुनाव आई-कार्ड के आधार पर जारी किया गया था। इस सीएएफ को कंपनी में सुरक्षित रखा गया था। इस दस्तावेज़ के साथ कोई हेरफेर नहीं किया गया था।

21.i.अपनी जिरह में, पीडब्लू-12 ने कहा कि पुलिस ने सीएएफ के बारे में कुछ भी पूछताछ नहीं की। वह सी. ए. एफ. के संरक्षक नहीं थे। यह सामान्य नियम है कि जिस व्यक्ति के नाम पर सिम जारी किया जाता है, यह माना जाता है कि वही व्यक्ति इसका उपयोग करता है।

<u>ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष</u>

22. विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। निचली अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में सफल रहा है जिसमें पीड़ित रवि कुमार का सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़ित को उसके स्कूल से उठाया और उसे हिमगंगे जल संयंत्र ले गए जहाँ उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

आखिरकार, सह-अभियुक्तों में से एक, विवेक उर्फ मोदी के इकबालिया बयानों के आधार पर, पीड़ित का शव भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार पाया गया। अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों और पीडब्लू-5 के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का सी. डी. आर./सी.ए. एफ., सूचना देने वाला जो पीड़ित की मां है, भी अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों के अपराध की ओर इशारा करता है और इसका समर्थन पीडब्लू-11, जो मामले के जांच अधिकारी थे और पीडब्लू-12, भारती एयरटेल लिमिटेड पटना के नोडल अधिकारी ने किया है। विद्वत विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि फिरौती की मांग की परिस्थितियाँ और अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों का उद्देश्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों का समर्थन करता है और इस प्रकार पीड़ित की कथित हत्या के साथ अभियुक्त की सांठगांठ साबित होती है। विद्वत विचारण न्यायालय ने इस प्रकार अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें पीड़ित के अपहरण और हत्या की साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराया।

<u>अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुति</u>

23. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने विभिन्न आधारों पर अपील के तहत निर्णय (जिसे इसके बाद 'विवादित निर्णय' के रूप में संदर्भित किया गया है) पर हमला किया है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सी. डी. आर. के आवश्यक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है और उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (बी) के प्रावधान के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रदर्श -11 के माध्यम से रिकॉर्ड में प्रस्तुत सीडीआर के दस्तावेजों में मास्टर सर्वर के आई. पी. पते का संकेत नहीं था। इसके अलावा, संबंधित सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा सर्वर आदि में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि साक्ष्य

अधिनियम की धारा 65(बी) का अनुपालन किया गया था। इसलिए, पीडब्लू-5 और अन्य के सेलफोन का सीडीआर इस मामले में एक विश्वसनीय सबूत नहीं होगा। विद्वान वकील ने दस्तावेजी साक्ष्य सी. ए. एफ. के संबंध में तर्क दिया और आपत्ति जताई कि सी. ए. एफ. में हेरफेर किया गया है इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष की ओर से यह दायित्व था कि वह अभियुक्त के अपराध को इंगित करने और उनकी बेगुनाही के अनुरूप किसी भी परिकल्पना को बाहर करने के लिए की प्रत्येक परिस्थितियों को साबित करे।

24. विद्वान वकील ने आगे कहा कि रितेश कुमार उर्फ विकास कुमार का नाम प्राथमिकी में नहीं है और घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल सिम उनके नाम पर नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ सीडीआर के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इकबालिया बयान दबाव बनाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दर्ज किया गया है, इसके अतिरिक्त रितेश कुमार का इकबालिया बयान विरोधाभासी है, क्योंकि अभियोजन साक्ष्य के अनुसार शव 05.10.2015 को प्रात 3:30 बजे बरामद किया गया, जबकि रितेश कुमार का इकबालिया बयान 04.10.2015 को रात्रि 11:30 बजे दर्ज किया गया है तथा यह भी रिकार्ड में आया है कि शव 4 अक्टूबर 2015 को दिन के समय बरामद किया गया। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और घटना में इस्तेमाल किया गया सिम संजीव कुमार सिंह के नाम से जारी किया गया है, जिन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। रितेश कुमार नामक अभियुक्त/अपीलार्थी से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है और उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है।

25. अभियुक्त/अपीलार्थी विवेक उर्फ मोदी की ओर से विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी विवेक उर्फ मोदी केवल दुकानदार है और मोबाइल मरम्मत का

काम कर रहा है, उसे अन्य अभियुक्त व्यक्तियों से कोई सरोकार नहीं है और उसने केवल सिम को अभियुक्त/अपीलार्थी को बेच दिया है। सिम जारी करने के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किसी भी अपराध की किसी भी श्रेणी में आता है।

26. विद्वान वकीलों ने आगे कहा कि तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष ने पीड़ित रवि कुमार के अपहरण के सबूत पेश किए। तत्पश्चात उसका शव बाईपास रोड एनएच 31, चक्रसालपुर से बरामद किया गया। अभियोजन पक्ष ने यह भी रिकॉर्ड पर लाने का प्रयास किया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन, यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर पेश नहीं की गई कि आरोपी/अपीलकर्ताओं ने पीड़ित रवि कुमार की हत्या को अंजाम दिया था। लड़के की हत्या के लिए आरोपी/अपीलार्थियों के खुलेआम किए गए कृत्य के लिए सबूतों की अनुपस्थिति ने अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह पैदा कर दिया। अभियोजन पक्ष के मामले में कमी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा।

27. इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का समय शव की बरामदगी से 36 से 72 घंटे पहले है पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर के निजी क्लिनिक का पता होता है जो इंगित करता है कि पोस्टमॉर्टम केवल टेबल वर्क है और कुछ और नहीं और यह अस्पताल में नहीं किया गया है। पोस्टमॉर्टम के समक्ष प्रस्तुत जांच रिपोर्ट ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की वास्तविकता पर संदिग्ध सवाल उठाया। जाँच रिपोर्ट में रामदेव शर्मा के हस्ताक्षर हैं, जो कोई और नहीं बल्कि राजीव कुमार शर्मा के पिता हैं, जो पहले प्राथमिकी के नामित आरोपी थे, यह ज्ञात नहीं है कि वह उस स्थान पर कैसे पहुंचे जहाँ शव बरामद किया गया था।इससे संदेह पैदा होता है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की तारीख और शव की बरामदगी की तारीख

एक दूसरे के विरोधाभासी है। इसलिए अभियोजन पक्ष के मामलों में संदेह का लाभ अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को दिया जाना चाहिए।

28. विद्वान वकील ने आगे दोहराया कि अपीलार्थी का नाम एफ. आई. आर. में नहीं था और एफ. आई. आर. पूरी तरह से संदेह के आधार पर दर्ज की गई थी। इसलिए, उसकी दोषसिद्धि कानूनी रूप से गलत है और उसे दरकिनार किया जाना उचित है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि बचाव पक्ष ने जे. जे. बी. केस नं. के माध्यम से गवाहों के बयान की प्रमाणित प्रतियां दाखिल की थीं। 2015 का सं. 191 जिसमें शेष अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि वे दोषी नहीं पाए गए थे।

<u>सूचना देने वाले की ओर से प्रस्तुति</u>

29. सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि आरोपी व्यक्तियों ने नाबालिग पीड़ित रवि कुमार का अपहरण/अपहरण कर लिया था, जब वह अपनी माँ से सत्तर लाख रुपये की भारी फिरौती लेने के दुर्भावनापूर्ण और बेईमान इरादे से अपने स्कूल जा रहा था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि पीडब्लू-5 प्रीति देवी, सूचना देने वाली पीड़ित की माँ है जो आरोपी/अपीलकर्ताओं की ओर से फिरौती की मांग की परिस्थितियों के साथ-साथ आरोपी/अपीलकर्ताओं की पीड़ित की माँ के साथ टेलीफोन पर बातचीत के सी. डी. आर. के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ को स्थापित करती है। इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि मृतक पीड़ित रवि कुमार की मां पीडब्लू-5 प्रीति देवी ने अपने जाँच-प्रमुख में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उसे अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं की ओर से फिरौती की रकम की मांग करते हुए तीन कॉल प्राप्त हुई थीं और इस तथ्य का समर्थन पीडब्लू-11 जितेंद्र कुमार ने भी पीडब्लू-5 प्रीति देवी को धमकी भरे कॉल प्राप्त होने के बिंदु पर किया है।

30. सूचनाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि इस मामले में सबूतों से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी विवेक उर्फ मोदी ने फिरौती के उद्देश्य से संजीव कुमार सिंह के नाम से जाली दस्तावेजों पर सिम जारी किया था। इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि यह कानून का नियम है कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य है। सूचना देने वाले के लिए विद्वान वकील अंत में प्रस्तुत करते हैं कि विवादित निर्णय और आदेश किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>राज्य की ओर से प्रस्तुति</u>

31. राज्य के लिए लर्नड एपीपी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी व्यक्तियों/अपीलार्थियों द्वारा रवि कुमार के अपहरण की परिस्थितियों को साबित कर दिया है क्योंकि वे नाबालिग निर्दोष पीड़ित लड़के को नाला रोड, बिहार पुलिस स्टेशन में स्थित हिमगंगे जल संयंत्र के कमरे में ले गए और गला घोंटकर क्रूर तरीके से उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं ने पीड़ित रवि कुमार के शव का निपटान करने का भी दुस्साहस किया। अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया कि आरोपी/अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद, पीड़ित के शव को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दोनों आरोपी व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं के कहने पर अपराध स्थल से बरामद किया गया था। इसके अलावा, आरोपी व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं ने पीड़ित रवि कुमार के शव के पास पड़े प्लास्टिक के काले तार के बारे में इकबालिया बयान दिए।ये परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से अपराध करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों दोनों की सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करती हैं। पीडब्लू-11 और पीडब्लू-12 के साक्ष्य भी अभियुक्तों/अपीलार्थियों के खिलाफ उनकी ओर से आपराधिक साजिश के लिए संदिग्ध परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं।

32. उन्होंने आगे कहा कि ये सभी परिस्थितियाँ यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त ने अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश रची। ***विक्रम सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में लॉर्डशिप ने 2010 में सभी एम. आर. (सी. आर. आई.) 982 (एस. सी.)*** लॉर्डशिप ने फिरौती के लिए नाबालिग लड़के के अपहरण की समान परिस्थितियों से निपटा है जिसमे इसी प्रकार हत्या कर दी गई थी। इस न्यायिक उदाहरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 120-बी के तहत दोषी ठहराया। अंत में उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपस्थित परिस्थितियाँ इस धारणा को उठाने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त केवल पीड़ित की हत्या को अंजाम देने वाले अपराधी हैं। आदेश किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं है और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>विचारणीय</u>

33. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों, मुखबिर के विद्वान वकीलों और राज्य के विद्वान एपीपी को सुना है और साथ ही ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

34. विचारण न्यायालय द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अभियोजन पक्ष का मामला उन साक्ष्यों पर आधारित है जो परिस्थितिजन्य प्रकृति के हैं जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अपील के तहत निर्णय के पैराग्राफ '16' में किया गया है। विद्वत विचारण न्यायालय के निष्कर्षों और राज्य के लिए अपीलार्थियों और विद्वत एपीपी के विद्वान वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या अभिलेख पर साक्ष्यों के आधार पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम रहा

है और रवि कुमार की मृत्यु की घटनाओं की आपराधिक श्रृंखला पूरी हो गई इस न्यायालय को ***शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की याद दिलाई जाती है। उक्त फैसले के पैराग्राफ '152' को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

> 152. उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, उन पर चर्चा करने से पहले हम आपराधिक मामले में आवश्यक प्रकृति, चरित्र और आवश्यक सबूत पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करते हैं।इस न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय है ***हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** इस मामले का इस न्यायालय द्वारा आज तक के कई निर्णयों में समान रूप से अनुसरण और अनुप्रयोग किया गया है उदाहरण के लिए, तुफैल (उर्फ) सिम्मी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले। हनुमंत के मामले में जे. महाजन ने जो कहा है, उसे निकालना उपयोगी हो सकता हैः
>
> "यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक

श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।""

35. ***दिलावर हुसैन और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (1991) 1 एससीसी 253*** के मामले में एक बार फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित किया है। पैराग्राफ '3 और 4 ***दिलावर हुसैन*** (सुप्रा) के मामले में फैसले इस प्रकार है:-

3. इन सब ने प्रस्तुतियों के दौरान थोड़ी भावना पैदा की।लेकिन भावनाएँ या भावनाएँ, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हों, न तो प्रासंगिक हैं और न ही अदालत में उनकी कोई जगह है। दोषमुक्ति या दोषसिद्धि आपराधिक श्रृंखला के सबूत या अन्यथा पर निर्भर करती है जिसमें हमेशा क्यों, कहाँ, कब, कैसे और कौन शामिल होता है। दोष को घर लाने के लिए जंजीर की प्रत्येक गाँठ को संदेह की छाया से परे साबित करना पड़ता है। इसमें कोई भी दरार या ढील अभियोजन को कमजोर कर देती है। प्रत्येक कड़ी, इतनी सुसंगत होनी चाहिए कि एकमात्र निष्कर्ष जो अनुसरण करना चाहिए वह यह है कि अभियुक्त दोषी है। हालांकि दोषी को बचना नहीं चाहिए। लेकिन विश्वसनीय साक्ष्य, सच्चे गवाहों और ईमानदार और निष्पक्ष जांच पर किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को भावनाओं को गढ़ने या शांत करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानव गरिमा के लिए घातक है और सामाजिक, नैतिक और कानूनी मानदंडों का विनाशकारी है।

अपराध की कठोरता या उसके निष्पादन में क्रूरता, चाहे वह कितनी भी घृणित और कठोर क्यों न हो, अपराध का निर्णय लेने में प्रतिबिंबित नहीं हो सकती।

4. सबूतों की सराहना के बारे में भी गलतफहमी प्रबल थी। प्रस्तुतियों पर ध्यान दिए बिना यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि गवाहों की विश्वसनीयता को एक ही मानदंड के साथ मापा जाना चाहिए, चाहे वह सामान्य अपराध हो या सांप्रदायिक उन्माद के कारण उत्पन्न होने वाला अपराध। कानून साक्ष्य देने या उसके मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं करता है। नियम एक और केवल एक ही है, अर्थात् क्या बयान ईमानदार और सच्चे हैं। क्या गवाह, जो इस मामले में घटना को देखने का दावा करते हैं, इस कसौटी पर खरे उतरते हैं? लेकिन इससे पहले अभियोजन पक्ष के संस्करण की सत्यता को छूने वाले कुछ कानूनी और सामान्य प्रश्नों का निपटारा किया जाना चाहिए ।

36. अपराध को साबित करने के लिए, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष को कथित अपहरण में अपीलार्थियों की संलिप्तता, फिरौती की उनकी मांग, गवाहों की उपस्थिति और घटना को देखने की संभावना और अपीलार्थियों की पहचान साबित करने की आवश्यकता होगी। उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों को जोड़ते हुए, ***देवी लाल बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 2019 एससी 688 में***, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि:

"परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में जहां दो विचार संभव हैं, एक अपराध की ओर इशारा करते हुए और दूसरा अपनी बेगुनाही की ओर इशारा करते हुए, अभियुक्त एक के लाभ का हकदार

है जो उसके लिए अनुकूल है।इसके अलावा, दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले, अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त को दोषी 'होना चाहिए' और केवल 'शायद' दोषी नहीं।

37. ***शिवाजी साहेबराव बोबडे बनाम राज्य महाराष्ट्र 1974 एस. सी. आर. (1) 489,*** उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 'हो सकता है' और 'होना ही चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है। इसलिए, भले ही अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ मजबूत संदेह पैदा करता है, यह सबूत का विकल्प नहीं हो सकता है।

38. उपर्युक्त कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम जांच करेंगे और विचार करेंगे-

(क) क्या अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे साबित हुई हैं;

(ख) क्या वे परिस्थितियाँ निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली प्रवृत्ति की हैं;

(ग) क्या उन परिस्थितियों को संचयी रूप से अब तक एक श्रृंखला के रूप में लिया गया है जो इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते हैं कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध आरोपी द्वारा किया गया था;

(घ) क्या वे केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप हैं; और

(ङ) क्या वे साबित होने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करते हैं।

39. अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के अवलोकन से यह स्थापित होता है कि मुकदमे में घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 शत्रुतापूर्ण हो गए। पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 मुखबिर से संबंधित हैं और अभियोजन पक्ष के बाकी गवाह पुलिस सदस्य हैं जो जांच दल का हिस्सा थे और डॉक्टर जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया था। पीडब्लू-12 एकमात्र स्वतंत्र गवाह है लेकिन उसने भी इस घटना को नहीं देखा। अभियोजन पक्ष अपना मामला अपीलार्थी-अभियुक्त के इकबालिया बयानों पर टिका हुआ है जिसके कारण शव की खोज हुई। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपीलकर्ताओं का नाम एफआईआर में नहीं था। यह भी आश्चर्य की बात है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट बिहार शरीफ में पीडब्लू-11 द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन जिन गवाहों की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई थी, वे लखीसराय के निवासी थे। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने उन गवाहों से पूछताछ नहीं की, जिनकी उपस्थिति में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट बनाई गई थी।

40. अभियुक्त के इकबालिया बयानों को आगे बढ़ाने के लिए की गई खोजों में से एक डेढ़ मीटर लंबा काला प्लास्टिक का तार था जिसका उपयोग कथित रूप से मृत पीड़ित का गला घोंटने में किया गया था। अपने मुख्य परीक्षण पैरा 6 में पीडब्लू-8 ने कहा है कि पुलिस दल ने दो गवाहों की उपस्थिति में जाँच रिपोर्ट तैयार की थी और प्लास्टिक के काले तार को जब्त कर लिया था। उन्होंने कहा कि जब्ती सूची पीडब्लू-11 द्वारा तैयार की गई थी, जो तत्काल मामले में जांच अधिकारी थे। डेढ़ मीटर लंबा काला प्लास्टिक का तार एक महत्वपूर्ण खोज थी, हालांकि इसका न तो अभियोजन पक्ष द्वारा जब्ती सूची में उल्लेख किया गया था और न ही इसे विद्वत निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया था। निचली अदालत ने कथित हथियार के प्रस्तुति नहीं करवा कर भी गलती की है। पीडब्लू-11 ने यह भी कहा कि पीड़ित के शव के पास बरामद काले तार पर उंगलियों के निशान को फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था। पी. डब्ल्यू.-7, जो जांच दल में भी थे, ने अपनी जिरह के

पैरा-12 में कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि काले तार को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था या नहीं या जपतिसूची में इसका उल्लेख किया गया था।

41. ***ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1660 में रिपोर्ट किए गए जसबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य*** के मामले में यह माना गया कि "हथियार को मौके पर सील कर दिया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कोई सबूत नहीं है कि हथियार को जब्त करने के बाद इसे ठीक से पुलिस स्टेशन के मलखाना में रखा गया था और मालखाने रजिस्टर पेश नहीं किया गया था, तो हथियार की जब्ती संदिग्ध है।" ***ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1578 में रिपोर्ट किए गए राजस्थान राज्य बनाम गुरमैल सिंह*** के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि "यदि यह सबूत से साबित नहीं हुआ कि जब्त किए गए हथियार को मालखाने में सीलबंद स्थिति में रखा गया था, तो अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो सकता है।.

42. हमें डर है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के व्यापक दायरे में अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य की जांच नहीं की है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से भौतिक विसंगतियां, व्यक्तियों के झूठे निहितार्थ और केवल संदेह के आधार पर उनका नाम लेना स्पष्ट है। तथ्य यह है कि ***शरद बिरधीचंद सारदा (सुप्रा) और दिलावर हुसैन (सुप्रा)*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले को नियंत्रित करने वाले पंचशील के सिद्धांतों के रूप में जो माना गया है, वह इस मामले में पूरी तरह से गायब है।

43. फिर से, ***पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए आई आर1990 एससी 79*** में, इस न्यायालय ने पुष्टि की कि जब कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:

"1. जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है, उन्हें पक्के तौर से और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए।

2. वे परिस्थितियाँ निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

3.संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और कोई और नहीं; और

4. दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण रूप से असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।

44. ***जहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य के मामले मे जो (1991) 3 एस. सी. सी. 27*** में प्रतिवेदित है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त को केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि वह कितना मजबूत हो सकता है। इस संबंध में ***ज़हरलाल*** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। पैराग्राफ '4' को तैयार संदर्भ के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध एक चौंकाने वाला है, लेकिन जहां तक कानूनी सबूत का संबंध है, अपराध की गंभीरता अपने आप में अधिक नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में पीड़ित के साथ आखिरी बार देखा गया व्यक्ति, जब तक कि प्रथम दृष्टया उसे दोषमुक्त करने वाली परिस्थितियां न हों, प्रमुख संदिग्ध होगा, लेकिन अंतिम न्यायिक निर्णय में संदेह, चाहे वह कितना भी मजबूत हो, को सबूत का स्थान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

45. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में, एकमात्र परिस्थिति अभियुक्त/अपीलार्थियों के खिलाफ संदेह है। वर्तमान मामले में, पी.डब्ल्यू.-11, जांच अधिकारी ने कहा है कि जिस मोबाइल फोन से कथित फिरौती कॉल की गई थी, वह संजीव कुमार सिंह से संबंधित पाया गया था। सिम का उपयोग कथित तौर पर अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा फिरौती की मांग के लिए धोखाधड़ी के तरीके से किया गया था। हालांकि, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने इस व्यक्ति, संजीव कुमार सिंह के बारे में कोई जांच नहीं की और न ही उनसे अभियोजन गवाह के रूप में पूछताछ की गई और न ही पुलिस द्वारा आरोपी के रूप में मुकदमे के लिए भेजा गया। सी. डी. आर. और सी. ए. एफ. से पता चलता है कि कथित मोबाइल नंबर-7321072463 और सूचनादाता के नंबर-9304447877 के बीच एक बातचीत हुई थी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि यह अपीलार्थी ही थे जिन्होंने कथित मोबाइल नंबर से कॉल किया था। जैसा कि पीडब्लू-11 द्वारा स्वीकार किया गया था, जांच अधिकारी , कोई वॉयस रिकॉर्डिंग पेश नहीं की गई जिससे पता चले कि फिरौती की मांग वास्तव में अपीलकर्ताओं/आरोपियों द्वारा स्वयं की गई थी।

46. वर्तमान मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता से निपटने के लिए, जो कि कॉल विवरण रिपोर्ट और सीएएफ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी अधिनियम की धारा 22-ए, धारा 65-ए और धारा 65-बी के आवश्यक कानूनी प्रावधानों में तल्लीन होना आवश्यक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 22-ए, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के रूप में मौखिक प्रवेश की प्रासंगिकता से संबंधित है, निम्नानुसार हैः

> *"22ए. जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के रूप में मौखिक प्रवेश प्रासंगिक है-इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के रूप में मौखिक प्रवेश प्रासंगिक नहीं हैं, जब तक कि उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाया जाता है।.*
>
> *"65ए. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्ष्य के रूप में विशेष प्रावधान-इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को धारा 65 बी के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा सकता है।*
>
> *"65बी. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता।*
>
> *इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी अभिलेख एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी जो एक कागज पर मुद्रित होती है, संग्रहीत, रिकॉर्ड की जाती है या कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया में प्रतिलिपि की जाती है (जिसे इसके बाद कंप्यूटर आउटपुट के रूप में संदर्भित किया जाता है) को भी एक दस्तावेज माना जाएगा, यदि इस धारा में उल्लिखित शर्तें संबंधित सूचना और कंप्यूटर के संबंध में संतुष्ट हैं और किसी भी कार्यवाही में मूल की किसी भी अंतर्वस्तु या उसमें वर्णित किसी भी तथ्य के साक्ष्य*

के रूप में, बिना किसी अतिरिक्त सबूत या मूल के उत्पादन के, स्वीकार्य होगी, जिसके लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य होगा।"

उप-धारा में निर्दिष्ट शर्तें;

(1) कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में निम्नलिखित होगा, अर्थात्:दस्तावेजों की सूची

क) सूचना युक्त कंप्यूटर आउटपुट कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान तैयार किया गया था जब कंप्यूटर का उपयोग कंप्यूटर के उपयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से की जाने वाली किसी भी गतिविधि के उद्देश्यों के लिए जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए नियमित रूप से किया जाता था।

ख) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित या जिस प्रकार से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की गई है, उस प्रकार की जानकारी को उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में नियमित रूप से कंप्यूटर में डाला गया था;

ग) उक्त अवधि के पूरे भौतिक भाग में, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था या, यदि नहीं, तो किसी भी अवधि के संबंध में जिसमें यह ठीक से काम नहीं कर रहा था या अवधि के उस हिस्से के दौरान काम नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इसकी सामग्री की सटीकता को प्रभावित करे; और

घ) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में कंप्यूटर में दी गई ऐसी जानकारी को पुनः प्रस्तुत करती है या उससे प्राप्त होती है।

(3) उप-धारा (2) के खंड (ए) में उल्लिखित उस अवधि में नियमित रूप से की गई किसी भी गतिविधि के प्रयोजनों के लिए जानकारी का भंडारण या प्रसंस्करण कंप्यूटर द्वारा नियमित रूप से किया जाता था, चाहे -

क) उस अवधि में काम करने वाले कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा; या

ख) उस अवधि में लगातार काम करने वाले विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा; या

ग) उस अवधि में लगातार काम करने वाले कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा; या

घ) किसी भी अन्य तरीके से, जिसमें उस अवधि में एक या एक से अधिक कंप्यूटरों और कंप्यूटरों के एक या एक से अधिक संयोजनों का क्रमिक संचालन शामिल है।

उस अवधि के दौरान उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक एकल कंप्यूटर के रूप में माना जाएगा और इस धारा में कंप्यूटर के संदर्भों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(4) किसी भी कार्यवाही में जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में बयान देना वांछित है, एक प्रमाण पत्र जो निम्नलिखित में से कोई भी काम कर रहा है, अर्थात -

क) बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करना और जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया था उसका वर्णन करना;

ख) उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उत्पादन में शामिल किसी भी उपकरण का ऐसा विवरण देना जो यह दिखाने के उद्देश्य से उचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था;

ग) उन मामलों में से किसी से निपटना जिससे उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं;

और संबंधित उपकरण के संचालन या प्रासंगिक गतिविधियों के प्रबंधन (जो भी उचित हो) के संबंध में एक जिम्मेदार आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने का तात्पर्य प्रमाण पत्र में बताए गए किसी भी मामले का प्रमाण होगा; और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए यह किसी मामले को बताने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार बताए जाने के लिए पर्याप्त होगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

क) जानकारी को कंप्यूटर को आपूर्ति के रूप में लिया जाएगा यदि इसकी आपूर्ति किसी उपयुक्त रूप में की जाती है और क्या इसकी आपूर्ति सीधे या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से की जाती है;

ख) क्या किसी अधिकारी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दौरान, जानकारी को उन गतिविधियों के अलावा अन्यथा संचालित कंप्यूटर द्वारा उन गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए संग्रहीत या संसाधित किए जाने की दृष्टि से प्रदान किया जाता है, वह जानकारी, यदि विधिवत रूप से उस कंप्यूटर को प्रदान की जाती है, तो उन गतिविधियों के दौरान उसे प्रदान की जाएगी;

ग) एक कंप्यूटर आउटपुट को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया माना जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से बनाया गया था।

47. ***अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल और अन्य [2020] 7 एससीआर 180*** में सर्वोच्च न्यायालय ने ***अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर [2014] 11 एससीआर 180*** में अपने निर्णय का उल्लेख किया। 399 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के प्रावधानों पर चर्चा की गई। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"धारा 65 बी (1) एक गैर-अस्थाई खंड के साथ खुलती है, और यह स्पष्ट करती है कि कोई भी जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित है, जो एक कागज पर मुद्रित है, संग्रहीत, रिकॉर्ड की गई है या कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया में प्रतिलिपि बनाई गई है, उसे एक दस्तावेज माना जाएगा, और मूल की सामग्री या उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, मूल के उत्पादन के आगे के प्रमाण के बिना किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगी, जिसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य होगा। डीमिंग फिक्शन का कारण

यह है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 द्वारा परिभाषित "दस्तावेज़" में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं हैं।

22. धारा 65बी(2) तब उन शर्तों को संदर्भित करती है जो कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में संतुष्ट होनी चाहिए, और बताती है कि 65बी (2 (ए)) से 65 (2 (डी)) शर्तों में शामिल होने के लिए परीक्षण यह है कि कंप्यूटर का नियमित रूप से जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाए ताकि विचाराधीन अवधि में नियमित रूप से की जाने वाली गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए।उप-धारा 2 (ए) से 2 (डी) में उल्लिखित शर्तों को संचयी रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

23. उप-धारा (4) के तहत, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है जो बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करता है और उस तरीके का वर्णन करता है जिसमें इसे प्रस्तुत किया जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उत्पादन में शामिल उपकरण का विवरण देता है ताकि यह दिखाया जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, या तो संबंधित डिवाइस के संचालन के संबंध में जिम्मेदार आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा; या कोई व्यक्ति जो “प्रासंगिक गतिविधियों” के प्रबंधन में है - जो भी उचित हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह के मामले को "इसे बताने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार" कहा जाना पर्याप्त होगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी (4) के तहत, यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित किसी भी कार्यवाही में बयान देना वांछित है, तो यह अनुमत है बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(क) एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जो बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करता है;

(ख) प्रमाण पत्र को उस तरीके का वर्णन करना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उत्पादन किया गया था;

(ग) प्रमाण पत्र को उस रिकॉर्ड के उत्पादन में शामिल उपकरण का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए;

(घ) प्रमाण पत्र को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी (2) के तहत उल्लिखित लागू शर्तों से निपटना चाहिए; और

(ड़) प्रमाण पत्र पर संबंधित उपकरण के संचालन के संबंध में एक जिम्मेदार आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

48. ये सभी सुरक्षा उपाय स्रोत और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित दो लक्षण हैं जिन्हें साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की मांग की जाती है। साक्ष्य अधिनियम मौखिक साक्ष्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाण पर विचार या अनुमति नहीं देता है यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत आवश्यकता का पालन नहीं किया जाता है, जैसा कि अब भारत में कानून है।

49. जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सी. डी. आर./सी. ए. एफ. पर जिला खुफिया इकाई द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो संबंधित दूरसंचार एजेंसी/आर. टी. एम. एस.

से ई-मेल के माध्यम से कंप्यूटर से उत्पन्न सी. डी. आर./सी. ए. एफ. के रूप में प्राप्त हुआ था, जो अपीलार्थियों पर दायित्व निर्धारित करने का आधार बना है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (5)(ए)(बी)(सी) में निहित कानून के अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया था, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (5)(ए)(बी)(सी) में कहा गया हैः

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

क) जानकारी को कंप्यूटर को आपूर्ति के रूप में लिया जाएगा यदि इसे किसी उपयुक्त रूप में आपूर्ति की जाती है और क्या इसे सीधे या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से आपूर्ति की जाती है;

ख) क्या किसी अधिकारी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दौरान, जानकारी को उन गतिविधियों के अलावा अन्यथा संचालित कंप्यूटर द्वारा उन गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए संग्रहीत या संसाधित किए जाने की दृष्टि से प्रदान किया जाता है, वह जानकारी, यदि विधिवत रूप से उस कंप्यूटर को प्रदान की जाती है, तो उन गतिविधियों के दौरान उसे प्रदान की जाएगी;

ग) एक कंप्यूटर आउटपुट को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया माना जाएगा, चाहे वह सीधे उसके द्वारा या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) किसी पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के माध्यम से उपयुक्त उपकरण से तैयार किया गया था।

50. अभियोजन पक्ष ने अधिकारियों को भेजे गए मेल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसे जिला खुफिया इकाई द्वारा प्रमाणित किया गया था, लेकिन जब कानून

यह निर्धारित करता है कि जिस व्यक्ति के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अभिरक्षा है या जो व्यक्ति इसे संचालित करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ऐसी प्रति को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष धारा 65 बी (5) के अनुपालन में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना सीधे रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रहा है। वैधानिक अधिदेश और उस पर सर्वोच्च न्यायालय (उपरोक्त) के निर्णयों के आलोक में, यह न्यायालय उन व्यक्तियों से आवश्यक प्रमाण पत्र के अभाव में सी. डी. आर. और सी. ए. एफ. की स्वीकार्यता को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है जिनके पास मोबाइल फोन की अभिरक्षा थी।

51. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तों के इकबालिया बयान जांच अधिकारी द्वारा रात 11 बजे 04.10.2015 पर दर्ज किए गए थे और उसी के आधार पर, पुलिस ने मृतक पीड़ित रवि कुमार का शव 05.10.2015 पर दोपहर 3 बजे बरामद किया। अभियोजन पक्ष के गवाह का यह संस्करण बहुत संदिग्ध है क्योंकि जांच अधिकारी उसी दिन मृतक/पीड़ित का शव बरामद नहीं करता है, जबकि आरोपी/अपीलार्थी का इकबालिया बयान पटना उच्च न्यायालय सी. आर. में 04.10.2015 रात्रि 11 पर दर्ज किया गया था। अपराह्न 3 बजे मृतक/पीड़ित का शव 05.10.2015 पर बरामद किया गया। अभिलेख पर अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी की तारीख और समय दिखाने वाला कोई गिरफ्तारी ज्ञापन नहीं है।

52. ***सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1400,*** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> *"82. उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष कानून के अनुसार खोजों को साबित करने और स्थापित करने में सक्षम रहा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इस प्रकार हैः*

"27. अभियुक्त से प्राप्त कितनी जानकारी साबित हो सकती है।– बशर्ते कि, जब किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का खुलासा किया जाता है, तो ऐसी जानकारी का इतना हिस्सा, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित किया जा सकता है।.

83. उपरोक्त अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के साक्ष्य में पहली और बुनियादी कमजोरी यह है कि उनमें से किसी ने भी अपीलार्थी द्वारा दिए गए सटीक बयान को पेश नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रासंगिक तथ्य का पता चला है।

84. यदि जाँच अधिकारी के बारे में यह कहा जाए कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अपनी मर्जी और इच्छा से हिरासत में रहते हुए यह बयान दिया कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ उसने अपराध के हथियार को छिपाया था, उसने अपराध का हथियार, शव को दफनाने का स्थान, कपड़े आदि छिपाए थे, <u>तो पहली बात जो जांच अधिकारी को करनी चाहिए थी, वह पुलिस स्टेशन में ही दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाना था। एक बार जब दो स्वतंत्र गवाह पुलिस थाने में उनकी</u> उपस्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आरोपी को उस स्थान को इंगित करने के संबंध में एक उचित बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए जहां उसने अपराध के हथियार आदि को छिपाया था। जब अभियुक्त अभिरक्षा में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों (पंच-गवाहों) के समक्ष ऐसा

बयान देता है तो अभियुक्त द्वारा दिए गए सटीक बयान या सटीक शब्दों को पंचनामे के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए जो जाँच अधिकारी कानून के अनुसार निकाल सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामे का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है ताकि यह विश्वास हो सके कि आरोपी द्वारा एक विशेष बयान उस स्थान को इंगित करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा व्यक्त करते हुए दिया गया था जहां अपराध के हथियार या अपराध करने में उपयोग की गई किसी अन्य वस्तु को छिपाया गया था। एक बार पंचनामे का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद पुलिस दल आरोपी और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच-गवाह) के साथ उस विशेष स्थान पर आगे बढ़ेगा जिसका नेतृत्व आरोपी कर सकता है। यदि उस विशेष स्थान से अपराध का हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु मिलती है तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामे का दूसरा भाग होगा। कानून इस तरह से जांच अधिकारी से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत खोज पंचनामा तैयार करने की अपेक्षा करता है। यदि हम जाँच अधिकारी के पूरे मौखिक साक्ष्य को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि मामले के सभी उपरोक्त प्रासंगिक पहलुओं में इसकी कमी है।

(जोर दिया गया)

53. जबकि इस मामले में, जब अभियुक्त/अपीलार्थियों का इकबालिया बयान दर्ज किया जा रहा था, तो जाँच अधिकारी द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थियों के इकबालिया बयान को विश्वास दिलाने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह को नहीं बुलाया गया था। ऐसी

परिस्थिति में, अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा दिया गया तथाकथित इकबालिया बयान साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा।

54. अभियोजन पक्ष के मामले में उपरोक्त कमियों के अलावा, यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई गिरफ्तारी ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की तारीख और समय दिखाया गया है। इसलिए, अभियोजन पक्ष शव की खोज से पहले आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी को साबित करने में विफल रहा है। जाँच अधिकारी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्तों ने अपना इकबालिया बयान दिया और उसी के आधार पर पुलिस दल ने चक रसलपुर, एन. एच.-31, बिहार शरीफ के पास सड़क पर एक झाड़ी के पीछे से रवि कुमार का शव बरामद किया। ***आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह और अन्य एआईआर 2019 एससी 546,***

सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

> “एक बार जब अभियुक्त का इकबालिया बयान तथ्यों के आधार पर अनैच्छिक पाया जाता है, तो इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) द्वारा प्रभावित किया जाएगा, जिससे इस तरह का इकबालिया बयान अस्वीकार्य हो जाएगा। यह आगे नोट किया गया कि आत्म-दोषपूर्ण साक्ष्य को स्वीकार करने पर प्रतिबंध है, लेकिन यदि यह किसी अपराध के संबंध में भौतिक वस्तुओं की बरामदगी की ओर ले जाता है, तो इसे अक्सर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार साक्ष्य मूल्य रखने के लिए लिया जाता है। शीर्ष अदालत ने आगे आगाह किया कि यदि इस तरह का बयान जांच अधिकारी के अनुचित दबाव और मजबूरी में दिया जाता है, तो इस तरह के बयान के साक्ष्य मूल्य को रद्द कर दिया जाता है जिस आधार पर प्राप्ति होती है।.

55. ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्यों के संचयी पठन पर, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्त-अपीलार्थियों के अपराध को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य लाने में विफल रहा है। भा.दं.सं. की धारा 364 ए और धारा 302 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों का अभाव है और पीड़ित के अपहरण और हत्या और विचाराधीन घटना के संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थियों की भूमिका के बीच संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं किया जा सका है ताकि अपीलार्थियों के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

56. नतीजतन, निचली अदालत के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

57. दोनों अपीलकर्ता, विवेक कुमार उर्फ विवेक उर्फ मोदी उर्फ राम विवेक कुमार, पुत्र नंद किशोर प्रसाद (आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 822/2021) और रितेश कुमार उर्फ विकास कुमार उर्फ विकास उर्फ रितेश, पुत्र मुकेश कुमार (आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 99/2022) हिरासत में बताए जा रहे हैं। यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

58. निचली अदालत के रिकॉर्ड के साथ इस फैसले की एक प्रति विद्वत निचली अदालत को वापस भेजी जाए।

59. दोनों अपीलों को स्वीकृत किया जाता है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायामूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायामूर्ति)

ब्रजेश कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।